has been sent back to his parent Cadre/State consequent upon the abolition/surrender of any post. Only those officers who have completed their normal tenures at the Centre or have been recalled by their respective cadres have been reverted to their respective State Cadres.

(b) The mode of determination of vacancies, state-wise, is through consultation with State Government. Some State Government have suggested a reduction in the intake of I.A.S. Officers. The number of I.A.S. Officers to be recruited through Civil Services Examination, 1991 has been marginally reduced.

गुजरात में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित किये गए लक्ष्य

1615. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे तथा अब तक कितने लक्ष्य प्राप्त किये गये हैं ;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारी कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का समुचित कार्यान्वयन न किये जाने के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री श्री जी० वेंकट स्वामी : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) जो कि गुजरात सहित सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा था, का वर्ष 1989-90 से जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०) नामक एक नए कार्यक्रम में विलय कर दिया गया है । योजना के अन्तर्गत प्रगति की निगरानी सृजित किए गए रोजगार के श्रम दिनों के रूप में की जाती है । वर्ष 1991-92 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत गुजरात के लिए निर्धारित 244.25 लाख श्रम दिनों के रोजगार सृजन के लक्ष्य की तुलना में 254.13 लाख श्रम दिनों का सृजन किया गया है । चूंकि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है इसलिए उपचारी कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1991-92 की अवधि के दौरान गुजरात में जवाहर रोजगार योजना निधियों के दुरुपयोग और योजना का समुचित कार्यान्वयन न किए जाने के बारे में मंत्रालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी ।

Godowns in Andhra Pradesh

1616. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of godowns sanctioned and completed in Andhra Pradesh under the "Scheme for setting up of Rural Godowns" and what was central assistance provided so far; and

(b) what is the target for the year 1992-93 in Andhra Pradesh under this scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) 446 rural godowns with a total storage capacity of 2.77 lakhs tonnes have been sanctioned in Andhra Pradesh under the 'Scheme for Setting up of Rural Godowns' so far. An amount of Rs. 3.60 crores has been released as central assistance for the purpose. Out of 446 godowns, construction of 246 godowns with a total storage capacity of 1.68 lakhs tonnes has been completed and the remaining godowns are at different stages of construction.

(b) The scheme stands transferred to State Sector with effect from 1-4-1992 alongwith a large number of schemes as part of the general policy decision of the Government.